

श्री क० गो० सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं माया है।

MR. SPEAKER : He says that his question was not answered. Can you remember the question and answer it ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Shri Damani's ?

MR. SPEAKER : No, not Shri Damani's. Anyway, do not worry; the questioner himself has forgotten it.

श्री मु० अ० खाँ : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बम्बई की एक फर्म ने बाहर से जो नायलोन इम्पोर्ट हुआ था और जो बम्बई से एक्सपोर्ट करना था उसको बम्बई से न भेज कर मद्रास से उसको भेजने की कोशिश की थी और मद्रास की कस्टमब्र थ्रॉटोरिटीज ने उसको सीज कर लिया था ? अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तो क्या वह जानकारी ले कर इसके बारे में बतायेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें सरकारी अफसर भी शामिल थे ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : यह बात बिस्कुज सही है और इस मामले को सी० वी० आई० के हवाले किया गया है।

श्री मु० अ० खाँ : क्या इसमें सरकारी अफसर भी शामिल थे ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : तहकीकात पूरी होने के बाद ही इसका पता चलेगा।

MR. SPEAKER : How can he say as to who is interested in it until the inquiry is completed ?

SHRI S. R. DAMANI : May I know from the hon. Minister whether the import of nylon is for industrial use or for civil consumption and, if it is for industrial use, for which industry it is going to be used and whether any substitute is being produced in the country which is in excess ? I would also like to know whether it is a fact that the STC has imported caustic soda which is in surplus and aluminium.... (Interruption)

MR. SPEAKER : Where does caustic soda come here ? The question is about nylon and you go to caustic soda.

SHRI S. R. DAMANI : I may be given a reply about nylon.

MR. SPEAKER : Next question.

INDIA ELECTRIC WORKS, CALCUTTA

\*852. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) when the management of the India Electric Works, Ltd., Calcutta was taken over by Government;

(b) whether accounts have been maintained year-wise since the take-over and if so, the profit or loss in this venture, year-wise;

(c) if the accounts have not been maintained the reasons therefor; and

(d) the production turned out in quantity as well as value, year-wise and the number of labour and other staff employed and the wages and remunerations paid to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2163/67].

श्री बेनी शंकर शर्मा : जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा गया है उसको देखने से मालूम होता है कि यह कम्पनी पंखे और अन्य बिजली का सामान बनाती है। सदन इस बात को जानता है कि देश और विदेश में पंखों की बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ रखा गया है उसे देखने से मालूम होता है कि पहले साल में 7 लाख 22 हजार का नफा हुआ था। उसके बाद के सालों में घाटा दिखाया गया है। 1962 में 16 लाख का घाटा था, 1963 में 11 लाख का था, 1964 में 8 लाख 14 हजार का घाटा था, 1965 में 14 लाख 55 हजार का घाटा था और 1966 में 35 लाख का घाटा हुआ था। देश और विदेश में पंखों की बड़ी मांग है और पंखे बनाने वाली कम्पनियों को काफ़ी मुनाफ़ा भी हो रहा है। उदाहरण के लिए उषा फ़्रीन बनाने वाली कम्पनी, जै इंजीनियरिंग वर्क्स लि० को ही

लीजिये। यह अपने मजदूरों को काफी अच्छी मजदूरी और बोनस आदि देती है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी वह कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस कंपनी में, जिसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, इतना घाटा क्यों हो रहा है।

**SHRI RAGHUNATH REDDI :** It is true that this company is not in a very happy state. For this purpose, I may humbly submit that, when the company got into troubled waters, it was taken over by the Government under the Industrial Development and Regulation Act on 11th July, 1960 and this period is now extended up to 10th January, 1968. For the purpose of understanding the economics of the operations of this industry, the Government of India had appointed a technical committee which had estimated that at least Rs. 2.5 crores will have to be spent to bring new machinery and also to get the factory on proper production lines. The Government of India has examined this and still the matter is to be decided whether they would be able to find money for this purpose. Besides this, the factory owes quite a lot of money to the State Bank of India. Therefore, as I said, the affairs of the company are not in a happy state.

—————

**SHORT NOTICE QUESTION**  
**INDUSTRIAL LICENSING POLICY**  
**COMMITTEE**

**S.N.Q. 17. SHRI SARJOO PANDEY :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Industrial Licensing Policy Committee, which was asked to conduct an inquiry into the licences issued to Birlas, has not met so far despite the assurance given by Government that the inquiry will be over within six months; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) :** (a) The Committee has in fact held five formal meetings already.

(b) Does not arise.

**श्री सरजू पाण्डेय :** प्रोफ़ेसर थाकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसके मेम्बरों की शिकायत है कि सरकारी अफ़सर उनके साथ को-आपरेट नहीं करते हैं और उनको जांच-पड़ताल को सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं। इस स्थिति में जांच-पड़ताल कैसे चलेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह कमेटी कब बनी और कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी ?

**श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद :** जैसा कि मानरेबल मेम्बरों को मालूम है, यह कमेटी 22 जुलाई, 1967 को एपायंट की गई और उसने सितम्बर से काम करना शुरू किया उसके बाद उसकी चार पांच मीटिंग्स हुई हैं। इस सिलसिले में जिन आफ़िसरों की जरूरत थी, उनकी भी एपायंटमेंट अक्टूबर के महीने में हो गई। जहां तक मेरा इल्म है, सब आफ़िसरों उस कमेटी को मदद दे रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। जब कोई डिफ़िकल्टी, मुश्किल, होती है, तो कमेटी के चेयरमैन या मेम्बर मुझ से या मेरे क्लौग, मिनिस्टर आफ़ स्टेट, से मिलते हैं और जहां तक मुमकिन हो सकता है, हम उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं।

**श्री सरजू पाण्डेय :** मंत्री महोदय ने कहा है कि अफ़सर कमेटी के सदस्यों के साथ को-आपरेट करते हैं, लेकिन मेरी सूचना यह है कि बहुत दिनों तक सदस्यों को कोई आफ़िस या दफ़्तर नहीं मिला और सरकारी आफ़िसरों आज तक उनके साथ को-आपरेट नहीं करते हैं।

अभी-अभी अख़बारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कैबिनेट कोई दूसरी कमेटी बनाना चाहती है और इस तरह से सरकार बिड़ला के तमाम लाइसेंसिज़ को सीगलाइज़ करने के फेर में लगी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समाचार में कहां तक सत्य है।